



दक्षिण दिल्ली के बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल में भीषण आग लगने से अब तक 21 लोगों की मौत

(जीएनएस)। नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट और उससे जुड़े फ्लोरिश स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल में बुधवार सुबह (3 जून 2026) भीषण आग लगने से अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। कई मरने वाले विदेशी नागरिक (सेंट्रल एशिया और अफ्रीका के) हैं। 37 से ज्यादा लोगों को बचाया गया, जिनमें कई की हालत गंभीर है। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। यह दिल्ली की हालिया आग की घटनाओं में सबसे घातक में से एक है।

दिल्ली फायर सर्विसेज (DFS) को सुबह करीब 8:50-9:45 बजे सूचना मिली। आग ग्राउंड फ्लोर/बेसमेंट के रेस्टोरेंट से शुरू हुई और तेजी से ऊपरी मंजिलों तक फैल गई। 6 मंजिला इमारत में आग तीन-चार फ्लोर तक पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों (वॉटर टैंकर और बोर्सर समेत) ने घंटों मशकत के बाद आग पर काबू पाया। रेस्क्यू ऑपरेशन में बेसमेंट से भी लोगों को निकाला गया। कई लोग ऊपरी मंजिलों से कूदकर बचने की कोशिश में घायल हुए। बताया जा रहा है कि मैक्स अस्पताल में गंभीर हालत में 15 लोग कठव में और 8 वेंटीलेटर पर। 10 पुलिस वाले भी अस्पताल में भर्ती। फरार रेस्टोरेंट मालिक पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। वहीं, होटल के मालिक लोकेश बजाज की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू हो चुकी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया और मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये मुआवजे की घोषणा की। दिल्ली एलजी तरनजीत सिंह संघु और अन्य अधिकारियों ने तत्काल राहत कार्यों का निर्देश दिया। दुर्घटना सम्बंधी जानकारी सुबह 8:50-9:45 बजे: आग लगने की सूचना। DFS ने तुरंत 7 गाड़ियां रवाना कीं, बाद में और बढ़ाई गईं। पहले घंटे: बेसमेंट से 6+ लोगों का रेस्क्यू। ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट और ऊपर होटल में फंसे लोग। दोपहर तक: 37+ बचाव, 21 मौतें कन्फर्म। कई विदेशी पर्यटक/मरीजों के परिवार होटल में ठहरे थे (AIIMS और मैक्स हॉस्पिटल के पास लोकेशन)। आग बुझाने के बाद फॉरेंसिक टीम और पुलिस जांच में जुटी। 10 बड़े सवाल: जवाब की तलाश

आग लगने की वजह क्या थी? प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट का शक है। बेसमेंट में रेस्टोरेंट की किचन/इलेक्ट्रिकल सिस्टम से शुरू हुई आग तेजी से फैली। धुआं और जहरीली गैस ने कई लोगों को घेर लिया। सटीक कारण फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलेगा। दिल्ली में गर्मियों में शॉर्ट सर्किट आग का आम कारण है। इमारत कितनी पुरानी और कैसी थी? मंजिला कमर्शियल-रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ग्राउंड फ्लोर पर लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट, ऊपर फ्लोरिश स्टे/मिकासो होम्स जैसा बेड एंड ब्रेकफास्ट। यह होटल अक्वटर-मैक्स के पास मरीजों के परिवारों के लिए लोकप्रिय था। लाइसेंस और परमिशन में क्या गड़बड़ी? यह सबसे बड़ा सवाल। रिपोर्ट्स के मुताबिक, होटल को सिर्फ 6 कमरों का लाइसेंस था, लेकिन 20-25 कमरे चल रहे थे (अनअथराइज्ड)। बेसमेंट का इस्तेमाल रेस्टोरेंट के लिए, लेकिन फायर सेफ्टी नॉर्म्स की अनदेखी का आरोप। टडऊ ट्रेड लाइसेंस, FSSAI, GST, फायर NOC आदि की जांच हो रही है। कई ऐसी इमारतों में अनधिकृत निर्माण और ओवरलोडिंग आम समस्या है। फायर सेफ्टी व्यवस्था कैसी थी? प्रारंभिक जानकारी में फायर एक्सटिंग्विशर, स्मोक डिटेक्टर, लेकिन पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट, ऊपर फ्लोरिश स्टे के मालिक अलग-अलग हैं। टडऊ, ऋरअक और

लेकिन पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट, ऊपर फ्लोरिश स्टे के मालिक अलग-अलग हैं। टडऊ, ऋरअक और कया यह पूरी तरह अनधिकृत था? रेस्टोरेंट रन कर रहा था, लेकिन होटल हिस्से में ओवर-कंस्ट्रक्शन और बिना पर्याप्त परमिशन के कमरे चलाने के आरोप। बेड-ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट का फायदा उठाकर नियमों की अनदेखी। दिल्ली में आग की घटनाएं क्यों दोहराती हैं? पिछले 6 महीने में 66 मौतें। मई 2024: विवेक बिहार ने बेबी केयर - 7 नवजातों की मौत। अन्य लाइसेंस की जांच में पिछले मुकदमे का कप्लायंस रिकॉर्ड पुलिस खंगाल रही है। अभी दोनों मालिकों के फरार होने की खबर है। ऐसी घटनाओं में अक्सर मालिक, बिल्डर और अधिकारियों की मिलीभगत सामने आती है। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट के पास फायर डिपार्टमेंट का टडउ ही था। कितने लोग अंदर थे और कितने फंसे? इमारत में 40-50 से ज्यादा लोग थे (रेस्ट + स्टाफ)। 37 बचाए गए, 21 की मौत हो गई। कई विदेशी

घायलों को अक्वटर, मैक्स, सेक्रेट आदि अस्पतालों में भर्ती। जिम्मेदार कौन? आगे क्या? मजिस्ट्रेट जांच, पुलिस ऋरअक फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। अगर लाइसेंस उल्लंघन, फायर सेफ्टी अनदेखी साबित हुई तो, मालिक, मैनेजर और संबंधित अधिकारी जिम्मेदार। दोषपूर्ण मानववध या लापरवाही के तहत कार्रवाई संभव। बड़े सबक? यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, सिस्टमिक फेलियर है। दिल्ली जैसे घने शहर में कमर्शियल इमारतों, होटलों और रेस्टोरेंट्स पर सख्त निगरानी जरूरी।

कारण: पुरानी वायरिंग, फायर टडउ की कमी, अनधिकृत निर्माण, ओवरलोडिंग, और निगरानी की कमी। टडऊ और DFS के बीच समन्वय की समस्या। राहत और मुआवजा? PM मोदी ने हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया है। वहीं, मरने वालों के परिवारों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार की आर्थिक सहायता राशी का ऐलान किया था। दिल्ली सरकार और LG ने मेडिकल मदद, जांच का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के मालवीय नगर में लगी आग की घटना में जान गंवाने वालों के प्रति शोक व्यक्त किया (जीएनएस)। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आगजनी की घटना को दुःखद बताया। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिवारों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि इस घटना में घायल हुए लोगों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट



सिप्रकलर और पर्याप्त एग्जिट की कमी बताई जा रही है। बेसमेंट का एक दरवाजा बंद होने से धुआं फंस गया। ऊपरी फ्लोरों पर पर्याप्त इमरजेंसी एग्जिट नहीं थे। DFS PRO ए.के. मलिक ने बताया कि टीम ने तेजी से रेस्क्यू किया, लेकिन स्ट्रक्चरल इश्यूज ने चुनौती बढ़ाई। मालिक कौन है? रिकॉर्ड क्या कहते हैं? लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट और जुड़े होटल के मालिक/ऑपरेटर की पहचान की जा रही है। अभी तक कोई आधिकारिक नाम सार्वजनिक नहीं, लहाख में नए अवसरों पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लेख को पीएम मोदी ने साझा किया (पीएम मोदी ने साझा किया) लहाख में नए अवसरों पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लेख को पीएम मोदी ने साझा किया, पीएम नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लहाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लहाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि यह लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लहाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। श्री मोदी ने लेख को ज्ञानवर्धक बताते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि देश वैश्विक स्तर पर 'वोकल टू लोकल' की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमतों पर कांग्रेस का आरोप लगाया है कि 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है।' कांग्रेस ने कहा, 'पीएम मोदी अपनी छवि को बचाने के लिए देश के सोने को बिकवा रहे हैं।' (जीएनएस)। नई दिल्ली: डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमतों पर कांग्रेस एक बार फिर मोदी सरकार पर हमलावर हुई है। कांग्रेस ने दावा किया है कि पीएम मोदी को अपनी छवि की चिंता सता रही है, इसलिए रिजर्व बैंक से कहकर देश का सोना बिकवा रहे हैं। ताकि रुपया 100 के पार न चला जाए। कांग्रेस ने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से बुधवार को पोस्ट करते हुए कहा, 'मोदी सरकार से रुपया संभल नहीं रहा है। किसी भी वक्त एक डॉलर 100 रुपये हो सकता है।' कांग्रेस ने पोस्ट में लिखा- 'फ्रक गिरता रुपया, विदेशी निवेशकों का भारत से बाहर जाना, कंपनियों का बंद होना, रोजगार की मारमारी, ये सब दिया है। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि उसके पास मौजूद भौतिक सोने का भंडार पहले की तरह 880.52 टन ही है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। आरबीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि रिजर्व बैंक ने सोना बेचा है, लेकिन यह जानकारी सही नहीं है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसके स्वर्ण भंडार से जुड़ी जानकारी नियमित रूप से मासिक बुलेटिन में प्रकाशित की जाती है और वर्तमान में भौतिक सोने का स्टॉक 880.52 टन पर स्थिर बना हुआ है। आरबीआई ने कहा कि उसके स्वर्ण भंडार का पूरा विवरण मासिक बुलेटिन में उपलब्ध रहता है, जिसे कोई भी व्यक्ति आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकता है। बैंक ने दोहराया कि अभी तक सोने के भौतिक भंडार में कोई कमी नहीं आई है।

योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने 24 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, बढ़ाया गया सरकारी वकीलों का भत्ता

(जीएनएस)। लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को उनके सरकारी आवास पर आयोजित कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। सरकारी वकीलों के भत्ते में बढ़ोतरी के साथ मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया और लाखों वाहन स्वामियों को बड़ी राहत दी गई है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने खाद्य एवं रसद विभाग की मक्का क्रय नीति के साथ ही कारागार विभाग, सिंचाई विभाग, आबकारी विभाग, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, कृषि व स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के प्रस्ताव को भी बड़ी राहत दी है। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 प्रति कुंतल तय किया गया। मक्का की सरकारी खरीद की अवधि 5 जून से 31 जुलाई तक रहेगी और कई जिलों में मक्का खरीद की व्यवस्था लागू होगी। कैबिनेट में बंदियों की मृत्यु पर मुआवजे की नई नीति का हरी झंडी दी। जेल में बंदी की मृत्यु एवं मुआवजा भुगतान नीति को मंजूरी दी गई है। 18 शहरों में GCC मॉडल पर इलेक्ट्रिक बसें चलेगी और बड़े शहरों में अउ इलेक्ट्रिक बसें का संचालन होगा। सरकारी वकीलों के मानदेय और भत्ते बढ़ाए गए, मोहनलालगंज में रजिस्ट्री दफ्तर के लिए जमीन मंजूर की गई और पांच जिलों में नई जेलों के निर्माण को मंजूरी मिली है।

सरकारी खरीद की अवधि 5 जून से 31 जुलाई तक रहेगी और कई जिलों में मक्का खरीद की व्यवस्था लागू होगी। कैबिनेट में बंदियों की मृत्यु पर मुआवजे की नई नीति का हरी झंडी दी। जेल में बंदी की मृत्यु एवं मुआवजा भुगतान नीति को मंजूरी दी गई है। 18 शहरों में GCC मॉडल पर इलेक्ट्रिक बसें चलेगी और बड़े शहरों में अउ इलेक्ट्रिक बसें का संचालन होगा। सरकारी वकीलों के मानदेय और भत्ते बढ़ाए गए, मोहनलालगंज में रजिस्ट्री दफ्तर के लिए जमीन मंजूर की गई और पांच जिलों में नई जेलों के निर्माण को मंजूरी मिली है।

लहाख में नए अवसरों पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लेख को पीएम मोदी ने साझा किया (पीएम मोदी ने साझा किया) लहाख में नए अवसरों पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लेख को पीएम मोदी ने साझा किया, पीएम नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लहाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लहाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि यह लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लहाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। श्री मोदी ने लेख को ज्ञानवर्धक बताते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि देश वैश्विक स्तर पर 'वोकल टू लोकल' की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमतों पर कांग्रेस का आरोप लगाया है कि 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है।' कांग्रेस ने कहा, 'पीएम मोदी अपनी छवि को बचाने के लिए देश के सोने को बिकवा रहे हैं।' (जीएनएस)। नई दिल्ली: डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमतों पर कांग्रेस एक बार फिर मोदी सरकार पर हमलावर हुई है। कांग्रेस ने दावा किया है कि पीएम मोदी को अपनी छवि की चिंता सता रही है, इसलिए रिजर्व बैंक से कहकर देश का सोना बिकवा रहे हैं। ताकि रुपया 100 के पार न चला जाए। कांग्रेस ने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से बुधवार को पोस्ट करते हुए कहा, 'मोदी सरकार से रुपया संभल नहीं रहा है। किसी भी वक्त एक डॉलर 100 रुपये हो सकता है।' कांग्रेस ने पोस्ट में लिखा- 'फ्रक गिरता रुपया, विदेशी निवेशकों का भारत से बाहर जाना, कंपनियों का बंद होना, रोजगार की मारमारी, ये सब दिया है। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि उसके पास मौजूद भौतिक सोने का भंडार पहले की तरह 880.52 टन ही है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। आरबीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि रिजर्व बैंक ने सोना बेचा है, लेकिन यह जानकारी सही नहीं है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसके स्वर्ण भंडार से जुड़ी जानकारी नियमित रूप से मासिक बुलेटिन में प्रकाशित की जाती है और वर्तमान में भौतिक सोने का स्टॉक 880.52 टन पर स्थिर बना हुआ है। आरबीआई ने कहा कि उसके स्वर्ण भंडार का पूरा विवरण मासिक बुलेटिन में उपलब्ध रहता है, जिसे कोई भी व्यक्ति आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकता है। बैंक ने दोहराया कि अभी तक सोने के भौतिक भंडार में कोई कमी नहीं आई है।

'मोदी ने बर्बाद कर दी भारत की अर्थव्यवस्था', रुपये की गिरती कीमतों पर कांग्रेस का प्रधानमंत्री पर आरोप

डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमतों पर कांग्रेस का आरोप लगाया है कि 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है।' कांग्रेस ने कहा, 'पीएम मोदी अपनी छवि को बचाने के लिए देश के सोने को बिकवा रहे हैं।' (जीएनएस)। नई दिल्ली: डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमतों पर कांग्रेस एक बार फिर मोदी सरकार पर हमलावर हुई है। कांग्रेस ने दावा किया है कि पीएम मोदी को अपनी छवि की चिंता सता रही है, इसलिए रिजर्व बैंक से कहकर देश का सोना बिकवा रहे हैं। ताकि रुपया 100 के पार न चला जाए। कांग्रेस ने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से बुधवार को पोस्ट करते हुए कहा, 'मोदी सरकार से रुपया संभल नहीं रहा है। किसी भी वक्त एक डॉलर 100 रुपये हो सकता है।' कांग्रेस ने पोस्ट में लिखा- 'फ्रक गिरता रुपया, विदेशी निवेशकों का भारत से बाहर जाना, कंपनियों का बंद होना, रोजगार की मारमारी, ये सब दिया है। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि उसके पास मौजूद भौतिक सोने का भंडार पहले की तरह 880.52 टन ही है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। आरबीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि रिजर्व बैंक ने सोना बेचा है, लेकिन यह जानकारी सही नहीं है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसके स्वर्ण भंडार से जुड़ी जानकारी नियमित रूप से मासिक बुलेटिन में प्रकाशित की जाती है और वर्तमान में भौतिक सोने का स्टॉक 880.52 टन पर स्थिर बना हुआ है। आरबीआई ने कहा कि उसके स्वर्ण भंडार का पूरा विवरण मासिक बुलेटिन में उपलब्ध रहता है, जिसे कोई भी व्यक्ति आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकता है। बैंक ने दोहराया कि अभी तक सोने के भौतिक भंडार में कोई कमी नहीं आई है।

रुपया, विदेशी निवेशकों का भारत से बाहर जाना, कंपनियों का बंद होना, रोजगार की मारमारी, ये सब दिया है, सिर्फ 2 हफ्ते में।' पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस ने कहा, 'ये सब मोदी की फर्जी छवि को बचाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि बहुत देर हो चुकी है और सच सबके सामने है।' 'मोदी ने बर्बाद की अर्थव्यवस्था': कांग्रेस कांग्रेस ने कहा, 'मोदी ने भारत की इकॉनमी को बर्बाद कर दिया है, इसके सबूत हैं और ये बस शुरूआत है।' RBI ने रिपोर्टों को किया खारिज हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को उन सभी मीडिया रिपोर्टों को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि केंद्रीय बैंक ने अपने स्वर्ण भंडार (गोल्ड रिजर्व) का एक हिस्सा बेच दिया है।

रुपया, विदेशी निवेशकों का भारत से बाहर जाना, कंपनियों का बंद होना, रोजगार की मारमारी, ये सब दिया है, सिर्फ 2 हफ्ते में।' पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस ने कहा, 'ये सब मोदी की फर्जी छवि को बचाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि बहुत देर हो चुकी है और सच सबके सामने है।' 'मोदी ने बर्बाद की अर्थव्यवस्था': कांग्रेस कांग्रेस ने कहा, 'मोदी ने भारत की इकॉनमी को बर्बाद कर दिया है, इसके सबूत हैं और ये बस शुरूआत है।' RBI ने रिपोर्टों को किया खारिज हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को उन सभी मीडिया रिपोर्टों को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि केंद्रीय बैंक ने अपने स्वर्ण भंडार (गोल्ड रिजर्व) का एक हिस्सा बेच दिया है।

रुपया, विदेशी निवेशकों का भारत से बाहर जाना, कंपनियों का बंद होना, रोजगार की मारमारी, ये सब दिया है, सिर्फ 2 हफ्ते में।' पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस ने कहा, 'ये सब मोदी की फर्जी छवि को बचाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि बहुत देर हो चुकी है और सच सबके सामने है।' 'मोदी ने बर्बाद की अर्थव्यवस्था': कांग्रेस कांग्रेस ने कहा, 'मोदी ने भारत की इकॉनमी को बर्बाद कर दिया है, इसके सबूत हैं और ये बस शुरूआत है।' RBI ने रिपोर्टों को किया खारिज हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को उन सभी मीडिया रिपोर्टों को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि केंद्रीय बैंक ने अपने स्वर्ण भंडार (गोल्ड रिजर्व) का एक हिस्सा बेच दिया है।

राहुल-खरगे व अनेक बड़े नेताओं ने कर्नाटक के नये सीएम डीके शिवकुमार को सोशल मीडिया पर दीं शुभकामनाएं

(जीएनएस)। नई दिल्ली: कर्नाटक कांग्रेस में चल रहा सियासी घमासान बुधवार को डी.के. शिवकुमार के सीएम पद की शपथ लेते ही थम गया। आठ बार के विधायक और कांग्रेस के संकटमोचक माने जाने वाले डी.के. शिवकुमार कर्नाटक के नए सीएम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने डी.के. शिवकुमार को कर्नाटक का नया सीएम बनने पर बधाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी बधाई दी।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की शपथ लेने पर, अपनी हार्दिक प्रतिक्रिया राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि मैं श्री राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि मैं श्री

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसी कड़ी में लोकसभा नेता

अपना भरोसा जताया है, और यह भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे लिखा कि मुख्यमंत्री श्री डी.के. शिवकुमार जी और मंत्रिपरिषद को हार्दिक बधाई, जो कर्नाटक की जनता की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस सांसद ने आगे लिखा कि श्री सिद्धारमैया जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनके नेतृत्व और सेवा ने कर्नाटक को मजबूत बनाया है और लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी बधाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी बधाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी बधाई दी।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसी कड़ी में लोकसभा नेता

अपना भरोसा जताया है, और यह भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे लिखा कि मुख्यमंत्री श्री डी.के. शिवकुमार जी और मंत्रिपरिषद को हार्दिक बधाई, जो कर्नाटक की जनता की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस सांसद ने आगे लिखा कि श्री सिद्धारमैया जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनके नेतृत्व और सेवा ने कर्नाटक को मजबूत बनाया है और लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसी कड़ी में लोकसभा नेता



कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसी कड़ी में लोकसभा नेता

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसी कड़ी में लोकसभा नेता

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसी कड़ी में लोकसभा नेता

गरवी गुजरात हिन्दी

JioTV CHENNAI NO. 2002

Jio Air Fiber

Jio Tv +

Jio Fiber

Daily Hunt

ebaba TV

Dish Plus

DTH live OTT

Rock TV

Airtel

Amezone Fire

Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही गरवी गुजरात हिंदी चैनल देखिये

पीएम मोदी की अपील का असर: सीएम मोहन के काफिले में पहली बार इलेक्ट्रिक कार शामिल, ग्रीन मोबिलिटी की ओर बढ़ाए कदम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के काफिले में पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया गया है, जो प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचत अपील से प्रेरित है।

(जीएनएस)। भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने की अपील का असर अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के काफिले में भी दिखाई देने लगा है।

मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक काफिले में पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके लिए महिंद्रा की अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक एसयूवी एश 9ी खरीदी गई है, जो बुधवार से मुख्यमंत्री के काफिले का हिस्सा बन गई है।

मुख्यमंत्री बुधवार शाम दिल्ली रवाना होते समय मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक इसी इलेक्ट्रिक कार में सफर करेंगे। महिंद्रा के अनुसार यह वाहन एक बार चार्ज होने पर 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर

सकता है। काफिला छोटा हुआ, डीजल की खपत घटी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद राज्य सरकार ने वीआईपी काफिलों में वाहनों की संख्या कम करने की पहल की थी। इसका सीधा



असर ईंधन खपत पर दिखाई दिया है।

गैरेज सुत्रों के अनुसार अप्रैल 2026 में जहां वीआईपी वाहनों में लगभग 24 हजार लीटर डीजल की खपत हुई थी, वहीं मई में यह घटकर 18 हजार लीटर रह गई। यानी एक माह में करीब 6 हजार लीटर डीजल

की बचत दर्ज की गई।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले ही अपने काफिले में शामिल वाहनों की संख्या 13 से घटाकर 7 कर चुके हैं।

उनकी इस पहल के बाद कई मंत्रियों और अधिकारियों ने भी कार-पूलिंग तथा कम वाहनों के उपयोग को बढ़ावा

मुख्यमंत्री के आधिकारिक काफिले में पहली बार किसी इलेक्ट्रिक कार को शामिल किया गया है। इसे सरकारी परिवहन व्यवस्था में ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए वाहन को तकनीकी जांच पूरी कर ली गई है। ड्राइवरों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियों ने भी आवश्यक परीक्षण कर लिए हैं।

आधुनिक सुविधाओं से लैस है एश 9ी

महिंद्रा एश 9ी को कंपनी की सबसे आधुनिक इलेक्ट्रिक कारों में गिना जाता है। इसमें 360 डिग्री कैमरा, पैनेोरमिक सनरूफ, फास्ट चार्जिंग तकनीक, एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स और स्मार्ट कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वाहन लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी उपयुक्त माना जा रहा है।

यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे? तारीख बताए चुनाव आयोग... हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार से भी मांगा जवाब

(जीएनएस)। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी पंचायत चुनाव में देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए निर्वाचन आयोग से पूछा है कि वह तारीख बताये की कब होंगे। साथ राज्य सरकार से ओबीसी आरक्षण को लेकर भी स्पष्टीकरण देने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार 10 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट पेश करे।

(जीएनएस)। लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार से पूछा है कि यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे, सरकार तारीख बताये. ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाने और उन्हें प्रशासक नियुक्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से तारीख बताने का आदेश दिया है. साथ ही राज्य सरकार से ओबीसी आरक्षण को लेकर भी स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई

10 जुलाई को होगी. दरअसल, राज्य सरकार के उस आदेश के खिलाफ लखनऊ बेंच में

ग्राम प्रधानों के कार्यकाल बढ़ने पर कोर्ट सख्त मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल



याचिका दाखिल की गई है, जिसमें ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाते हुए प्रशासक नियुक्त किया गया है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि पंचायत चुनाव कब होंगे, तारीख बताई जाए. साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ओबीसी आरक्षण को लेकर भी स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई

6 महीने बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला. कोर्ट ने राज्य सरकार को पंचायत चुनाव को देखते हुए बनाए गए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अगली सुनवाई पर 10 जुलाई को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया. स्थानीय अधिकारी की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया. याचिका ने सरकार के

इस आदेश को कानून की मंशा के खिलाफ बताते हुए चुनौती दी है.

प्रदेश में वर्तमान ग्राम प्रधानों को पंचायत चुनाव होने और नए प्रधान चुने जाने तक प्रशासक नियुक्त करने के राज्य सरकार के 25 मई के आदेश को चुनौती दी गई है. जिस पर हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है. याचिका के मुताबिक, यूपी पंचायत राज अधिनियम की धारा 12 के तहत प्रधानों का कार्यकाल उनके शपथ लेने से केवल 5 साल का ही हो सकता है. लेकिन सरकार ने समय पर पंचायत चुनाव न करा कर मौजूद प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया है. ऐसा करके एक प्रकार से उनका कार्यकाल अनिश्चितकाल तक बढ़ा दिया है, जो विधि विरुद्ध है. याचिका में मांग की गई कि पहले यदि पंचायत चुनाव नहीं हो पाते थे तो एडीओ पंचायत या किसी अन्य अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया जाता था. उसी प्रकार इस बार भी होना चाहिए था.

लखनऊ: भाजपा नेता की हत्या मामले में CCTV से मिले अहम सुराग, चार आरोपियों की तलाश में पुलिस

लखनऊ के विभूतिखंड स्थित जलवा क्लब के बाहर भाजपा नेता शिवम सिंह की हत्या मामले में पुलिस ने चार और संदिग्ध आरोपियों की पहचान की है।

(जीएनएस)। लखनऊ। विभूतिखंड स्थित जलवा क्लब के बाहर भाजपा नेता शिवम सिंह की हत्या के मामले में पुलिस जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब तक की तपतीश में पुलिस ने चार और संदिग्ध आरोपियों को चिह्नित किया है। सीसी फुटेज और गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ के आधार पर उनकी पहचान की गई है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है।

विभूतिखंड पुलिस के अनुसार, हत्याकांड के मुख्य आरोपित और 25 हजार रुपये के इनामी अनुज सिंह को चंडौली के मुगलसराय क्षेत्र से गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके

कब्जे से एक तमंचा भी बरामद हुआ था। इसके अलावा विभूतिखंड पुलिस



इस मामले में अलीगंज निवासी शांतनु उर्फ अंकित रावत, हनी तिवारी उर्फ विवेक तथा आजमगढ़ निवासी विवेक सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

जांच के दौरान पुलिस ने जलवा क्लब और उसके आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज के सामने आया कि घटना के समय

गिरफ्तार आरोपितों के अलावा कुछ अन्य युवक भी मौके पर मौजूद थे।

वह 25 मई की रात अपने दोस्तों निलेश, जीशान और एक अन्य साथी के साथ विभूतिखंड स्थित जलवा क्लब में पार्टी करने आए थे। 26 मई की सुबह करीब तीन बजे क्लब से बाहर निकलने के दौरान सिरपेट पीने को लेकर विवाद हो गया था। आरोप है कि इसी विवाद में हमलावरों ने ईंट-पत्थरों से हमला कर शिवम की हत्या कर दी थी। हाईप्रोफाइल हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री स्तर तक नाराजगी जताई गई थी।

इसके बाद एसीपी विभूतिखंड विनय द्विवेदी, तत्कालीन इंस्पेक्टर अमर सिंह समेत दो उपनिरीक्षकों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाया गया था। डीसीपी पूर्वी डॉ. दीक्षा शर्मा ने बताया कि मामले में कुछ और लोगों की पहचान की गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और जल्द ही अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

भारत से नेपाल ले जा सकेंगे 5 गुना ज्यादा सामान, टैक्स फ्री

(जीएनएस)। नेपाल सरकार ने भारत-नेपाल सीमा से आने-जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने सड़क मार्ग से सीमा पार करने वाले लोगों के लिए ड्यूटी-फ्री सामान की सीमा 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है। पिछले नियम के कारण सीमा इलाकों में रहने वाले लोगों, छोटे व्यापारियों और रोजाना आने-जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी हो रही थी।

कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे और मामला नेपाल संसद तक पहुंच गया था। लगातार बढ़ते दबाव के बाद सरकार ने नियम में बदलाव किया है। नए फैसले को सीमा क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

क्या बदला है नया नियम? नेपाल के वित्त मंत्रालय ने राजपत्र में नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि अब सड़क मार्ग से सीमा पार करने वाले यात्री 500 रुपये तक के निजी इस्तेमाल के सामान को बिना कस्टम ड्यूटी के ला और ले जा सकेंगे। इससे पहले यह सीमा सिर्फ 100 रुपये थी। नए नियम के तहत कस्टम अधिकारी सामान की जरूरत और उपयोग को देखकर उसे ड्यूटी-फ्री अनुमति दे सकते हैं। हालांकि यह सुविधा सिर्फ

सीमित मूल्य के निजी सामान पर लागू होगी और बड़े कमर्शियल सामान पर नहीं। पुराने नियम पर क्यों हुआ था

विरोध? मई 2025 में नेपाल सरकार ने 100 रुपये से ज्यादा कीमत का सामान बिना टैक्स लाने पर रोक लगा दी थी। इस नियम का सबसे ज्यादा असर सीमा



क्षेत्रों में बढ़ते विरोध के बाद यह मुद्दा नेपाल संसद में भी उठा था। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले ने माना था कि यह नियम पिछली सरकार के समय बनाया गया था और मौजूदा सरकार इसमें बदलाव पर विचार कर रही है। उन्होंने संसद में

व्यापारियों और स्थानीय संगठनों ने कहा था कि 100 रुपये की सीमा व्यावहारिक नहीं है और इससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं।

संसद तक पहुंचा था मामला सीमा क्षेत्रों में बढ़ते विरोध के बाद यह मुद्दा नेपाल संसद में भी उठा था। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले ने माना था कि यह नियम पिछली सरकार के समय बनाया गया था और मौजूदा सरकार इसमें बदलाव पर विचार कर रही है। उन्होंने संसद में भरोसा दिलाया था कि सीमा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राहत देने का प्रयास किया जाएगा। अब सरकार ने सीमा बढ़ाकर 500

सीएम योगी ने की रवि किशन की तारीफ, बोले- 'फिल्म भले फ्री में न दिखाएं, लेकिन हर कार्यक्रम में रहते हैं मौजूद'

गोरखपुर में ₹208 करोड़ की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद रवि किशन की जमकर तारीफ की।

(जीएनएस)। गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) क्षेत्र में ₹208 करोड़ की लागत से तैयार विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, ईडब्ल्यूएस (एहर) और एलआईजी (छक्क) आवासीय परिसर समेत कई विकास योजनाओं की सीमागत दी। कार्यक्रम के आर्वटन पत्र वितरित किए और उक्तखक कौशल केंद्र से प्रशिक्षित छात्रों को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए। इस मौके पर गोरखपुर के सांसद और भी अभिनेता रवि किशन भी मौजूद रहे, जिनकी मुख्यमंत्री ने मंच से तारीफ करते हुए सराहना की।

करोड़ों की परियोजनाओं की दी सीमागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गीडा क्षेत्र में विकसित की

जा रही परियोजनाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति देंगी। उन्होंने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स को प्रदेश के औद्योगिक



विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अत्याधुनिक फ्लैटेड फैक्ट्री में एक ही परिसर के भीतर एमएसएमई क्षेत्र के 100 से अधिक उद्योग संचालित हो सकेंगे। यह मॉडल न केवल प्रदेश बल्कि देश और वैश्विक स्तर पर भी औद्योगिक विकास का अनुकरणीय उदाहरण बनेगा।

लाभार्थियों और छात्रों को सौंपे प्रमाण-पत्र कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एहर और छक्क आवासीय योजनाओं के लाभार्थियों को आर्वटन पत्र वितरित किए। इसके अलावा

औद्योगिक भूखंड आवंटियों को भी दस्तावेज सौंपे गए। उक्तखक कौशल केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रमाण-पत्र देकर



मुख्यमंत्री ने उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

मंच से रवि किशन की तारीफ कार्यक्रम में सांसद रवि किशन की मौजूदगी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हक्के-फुल्के अंदाज में उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा, "भले ही आपको ये फ्री में फिल्म न दिखाते हों, लेकिन सभी कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। योजनाओं में सक्रिय भागीदारी दिखाते हैं।" मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों ने

तालियां बजाकर प्रतिक्रिया दी। 'काम करने का जज्बा है रवि किशन में'

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि रवि किशन उनसे कह रहे थे कि यदि मैं कहीं तो वह इस भीषण गर्मी में नंगे पैर पदयात्रा भी निकाल सकते हैं। इस पर सीएम ने जवाब दिया कि पहले वारिश हो जाने दें, उसके बाद इस बारे में विचार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रवि किशन में काम करने का विशेष जज्बा है और वह एक सांसद के रूप में अपने दायित्वों का बेहतर ढंग से निर्वहन करना जानते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मंच पर इतनी गर्मी होने के बावजूद रवि किशन लगातार भाषण दिए जा रहे हैं।

औद्योगिक विकास को मिलेगी नई रफ्तार मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पूर्वांचल को औद्योगिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। गीडा में विकसित हो रही नई परियोजनाएं निवेश, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देंगी। उन्होंने विश्वास जताया कि इन योजनाओं से क्षेत्र के हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

सीएम ने जनता दर्शन में, भूमि संबंधी प्रकरणों में लापरवाही पर सीएम योगी सख्त, अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में भूमि संबंधी शिकायतों पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने डीएम को निर्देशित किया कि भूमि संबंधी शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

(जीएनएस)। लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में भूमि संबंधी शिकायतों पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने डीएम को निर्देशित किया कि भूमि संबंधी शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रकरण की गंभीरता के अनुसार संबंधित के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डीएम को कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश मुख्यमंत्री ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। कुछ लोगों ने जमीन से जुड़े मामलों में राजस्व कर्मियों की तरफ से लापरवाही किए जाने की शिकायत की तो उन्होंने डीएम को तत्काल कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इस मौके पर इलाज के

लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे लोगों से उन्होंने कहा कि सरकार इलाज में पूरी मदद करेगी। इसके लिए जरूरतमंद लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा और



इसके बाद भी जरूरत पड़ी तो विवेकाधीन कोष से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जरूरतमंद, पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि उन्हें इलाज के लिए परेशान न होना पड़े। सीएम योगी ने 150 लोगों से की मुलाकात जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 150 लोगों से मिले। उनके पास जाकर उनकी समस्याएं सुनीं। उनके प्रार्थना पत्रों का अवलोकन कर समस्या, शिकायत का संज्ञान लिया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिया कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है।



द्वारा मकान से बेदखल किए जाने की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा कि मकान पर महिला का कब्जा दिलाया जाए। उन्होंने अलग-अलग मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित करते हुए निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और संतुष्टिप्रद होना चाहिए। जरूरतमंद लोगों का जल्द बनवाए जाए आयुष्मान कार्ड-सीएम योगी जनता दर्शन में एक महिला ने मां

के इलाज के लिए सहायता देने का निवेदन किया। मुख्यमंत्री ने आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा। महिला ने बताया कि उसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। इस पर सीएम ने मौके पर मौजूद अफसरों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द इनका आयुष्मान कार्ड बनवाया जाए, अधिकारी हर जरूरतमंद का आयुष्मान कार्ड बनवाएं, ताकि उन्हें इलाज के लिए परेशान न होना पड़े। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर आए लोगों को मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि उन्हें विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

सीएम योगी ने की गोसेवा गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान बुधवार सुबह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही। सुबह गुरु गोरखनाथ और अपने ब्रह्मलीन गुरुदेव महंत अवैद्यनाथ जी का आशीर्वाद लेने के बाद सीएम योगी ने मंदिर की गोशाला में गोसेवा की। गोवंश की गोशाला से से गुड़-रोटी खिलाकर उन पर स्नेह बरसाया। बच्चों को दी चॉकलेट इसी क्रम में मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए उन्होंने परिजनों के साथ आए बच्चों को पास बुलाकर उन्हें चॉकलेट दीं और उनसे पढ़ाई के बारे में बातचीत की। सीएम ने बच्चों को खूब पढ़ने-आगे बढ़ने का आशीर्वाद भी दिया।

सहारा शहर लीज रद्द मामला, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और लखनऊ नगर निगम को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा शहर की लीज रद्द कर कब्जा लेने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और लखनऊ नगर निगम से जवाब तलब किया है।

(जीएनएस)। लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा शहर की लीज रद्द कर के उसका सेसस सहारा इंडिया कर्माश्रियल कारपोरेशन की ओर से दाखिल एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई करते हुए गत 29 मई को पारित किया। मामले की सुनवाई के बाद पीठ ने राज्य सरकार, लखनऊ नगर निगम, नगर आयुक्त एवं नगर निगम के प्रभारी अधिकारी संपत्ति को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। इस पर कब्जा लेने के मामले में राज्य सरकार और लखनऊ नगर निगम को नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को करने को कहा है। गौरतलब है कि सहारा शहर की जमीन का कब्जा वापस लेने के बाद राज्य सरकार वहां पर नई विधानसभा बनाने पर विचार कर रही है। यह आदेश चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जायमाल्या बागची एवं जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने

सेसस सहारा इंडिया कर्माश्रियल कारपोरेशन की ओर से दाखिल एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई करते हुए गत 29 मई को पारित किया।



कब्जा लेने के मामले में राज्य सरकार और लखनऊ नगर निगम को नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को करने को कहा है। गौरतलब है कि सहारा शहर की जमीन का कब्जा वापस लेने के बाद राज्य सरकार वहां पर नई विधानसभा बनाने पर विचार कर रही है। यह आदेश चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जायमाल्या बागची एवं जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने

उसका कब्जा लेने के नगर निगम के आदेशों के खिलाफ याचिका को सुनवाई योग्य न होने के आधार पर खारिज दिया था और कहा कि चूंकि सहारा सेबी विवाद में यह विवाद भी शामिल है, लिहाजा उसके हाथ बंधे हैं और मामले को सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है।

दरअसल, सहारा ने नगर निगम के आठ सितंबर, 2025 को जारी एक आदेश को चुनौती दी थी जिससे उसने सहारा को 22 अक्टूबर 1994 को दी गई जमीन की लीज को खारिज कर दिया था और 11 सितंबर, 2025 को आदेश जारी करने का आदेश उक्त जमीन को खाली कराने का आदेश भी कर दिया था। सहारा की ओर से तर्क दिया गया था कि दो सितंबर, 2017 को एक आर्बिट्रेशन मामले में इसी जमीन को लेकर उसके हक में आदेश पारित हो चुका था किंतु नगर निगम ने उस आदेश की अनदेखी करके गलत तरीके से पट्टे को खारिज किया था जबकि वह उसका सम्यक बढाने के लिए आवश्यक पैसा जमा करने को तैयार था।

जी7 समिट: रिशतों की बर्फ पिघलेगी? महीनों बाद एक मंच पर दिख सकते हैं मोदी और ट्रंप

फ्रांस में 15-17 जून को होने वाले ऋषिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आमने-सामने आने की संभावना है। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत के बीच यह मुलाकात रिशतों को नई दिशा दे सकती है। (जीएनएस)।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अगले सप्ताह होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में मुलाकात की संभावना बन रही है। फ्रांस की मेजबानी में 15 से 17 जून तक आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में दोनों नेताओं की मौजूदगी की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि, दोनों देशों की ओर से अब तक औपचारिक द्विपक्षीय बैठक तय नहीं की गई है।

सूत्रों के अनुसार भारत और

अमेरिका सम्मेलन के इतर मोदी-ट्रंप की मुलाकात की संभावनाएं तलाश रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के



राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन समेत अन्य G7 नेताओं के साथ भी अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें हो सकती हैं। ऐसे में G7 सम्मेलन वैश्विक कूटनीति का अहम मंच बनने जा रहा है।

फरवरी 2025 के बाद नहीं हुई दोनों नेताओं की मुलाकात मोदी और ट्रंप की आखिरी

मुलाकात फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे के दौरान हुई थी। इसके बाद व्यापार, भारत द्वारा रूसी

हाल के महीनों में दोनों देशों के संबंधों में सुधार के संकेत मिले हैं। पिछले महीने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका आने का निमंत्रण दिया था। हालांकि भारत ने अब तक सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया है कि प्रधानमंत्री ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया है या नहीं।

व्यापार समझौते और G20 पर भी नजर भारत और अमेरिका इस समय द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत कर रहे हैं, जिस पर पिछले एक साल से चर्चा चल रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के दिसंबर में फ्लोरिडा में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होने की संभावना है। ऐसे में G7 सम्मेलन दोनों नेताओं के बीच भविष्य की कूटनीतिक दिशा तय करने में अहम साबित हो सकता है।

झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने से लखनऊ में बच्ची की गई जान

राजधानी में झोलाछाप डॉक्टर पर लगाम नहीं लग पा रही है। ताजा मामला फैजुल्लागंज स्थित पुराना दाऊदनगर का है। जहां छह साल की मासूम सौम्या विश्वकर्मा की इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई। (जीएनएस)।

लखनऊ। राजधानी में झोलाछाप डॉक्टर पर लगाम नहीं लग पा रही है। ताजा मामला फैजुल्लागंज स्थित पुराना दाऊदनगर का है। जहां छह साल की मासूम सौम्या विश्वकर्मा की इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई।

परिवारीजनों का आरोप है कि इलाके के झोलाछाप डॉक्टर की दवा से बच्ची की हालत बिगड़ी थी। नाराज परिवारीजनों ने

क्लीनिक के बाहर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया।

इंजेक्शन के बाद तबियत हुई खराब

मामा कौशल के मुताबिक, भांजी सौम्या को बीते सोमवार सुबह बुखार को तेज होने पर मां गुड़िया ने बच्ची को

नजदीक मेडिकल स्टोर लेकर पहुंची। जहां मेडिकल स्टोर का संचालक खुद को डॉक्टर बताता था। उसने बच्ची की सेहत की जांच के

बाद इंजेक्शन लगाया। वहीं, दवा देने के बाद फीस के नाम पर 100 रुपये वसूले। घर पहुंचने के बाद मां ने

बेटी को एक खुगक दवा खिलाई। कुछ समय बाद बेटी की तबीयत बिगड़ने लगी। उसका शरीर नीला पड़ने लगा। परिवार के लोग बच्चे को लेकर दूसरे अस्पताल पहुंचे, जहां

कुछ देर बाद सौम्या की मौत हो गई।

पिता अनूप ने मेडिकल स्टोर संचालक पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया। वहीं, नाराज परिवारीजन शव लेकर मेडिकल स्टोर पहुंचे और हंगामा किया। माहौल बिगड़ता देख झोलाछाप मेडिकल स्टोर बंद कर फरार हो गया। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह परिवारीजनों को समझाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डिप्टी सीएमओ डॉ. एपी सिंह के मुताबिक मामला गंभीर है, आरोपों की जांच कराई जायेगी।

लखनऊ में बनेगा 350 बेड का आधुनिक ट्रॉमा सेंटर, एलडीए ने दी 16 हजार वर्ग मीटर जमीन

लखनऊ में लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को शहीद पथ किनारे 350 बेड का आधुनिक लेवल-1 ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए भूमि आवंटित की गई है।

(जीएनएस)।

लखनऊ। राजधानी सहित प्रदेशभर के रोगियों के लिए अच्छी खबर है। इलाज की आस में लखनऊ पहुंचने वाले गंभीर मरीजों को अब न तो बेड के लिए घंटों इंतजार करना होगा और न ही स्ट्रेचर पर रात गुजारनी होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को शहीद पथ किनारे लेवल-एक ट्रॉमा सेंटर के लिए भूमि आवंटित कर दी है। गोमतीनगर विस्तार सेक्टर-सात में मातृ एवं शिशु अस्पताल के सामने

करीब 16 हजार वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर 350 बेड का आधुनिक ट्रॉमा सेंटर बनेगा।

मौजूदा समय में सिर्फ केजीएमयू में ही लेवल-एक ट्रॉमा सेंटर है, जहां 450 बेड के सापेक्ष में तीन-चार गुणा अधिक मरीजों का दवाव है। एएसजीपीजीआई में ट्रॉमा सेंटर में 156 बेड की सुविधा है। ऐसे में लोहिया में लेवल-एक ट्रॉमा सेंटर बनने से काफी हद तक बेड की कमी पूरी की जा सकेगी।

इस भूमि पर निमाणाधीन फ्लॉवर वैली को दूसरी जगह शिफ्ट किया

जाएगा। अब भूमि को सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग में परिवर्तित किया जाएगा।

दूसरा सबसे बड़ा सरकारी चिकित्सा संस्थान होगा

लोहिया लोहिया संस्थान शहीद पथ



किनारे अपने परिसर में ही 1010 बेड का नया अस्पताल भी बनाने जा रहा है, जिसके निर्माण के लिए पिछले माह ही योगी कैबिनेट से मंजूरी मिली है। जुलाई आखिरी सप्ताह या अगस्त के शुरूआत में मुख्यमंत्री सात मंजिला भवन की नींव रखेंगे।

प्रस्तावित ट्रॉमा सेंटर नए अस्पताल के टीके सामने बनेगा। दरअसल, इस परिसर में बनने वाले अस्पताल में सभी ब्रांड स्पेशलिटी विभागों का संचालन होगा। साथ ही यहां पर 100 बेड का एडवॉंस क्रिटिकल केयर मेडिसिन यूनिट के भवन का निर्माण लगभग पूरा हो

चुका है, जिसे 15 अगस्त तक शुरू करने की तैयारी है।

मौजूदा समय में लोहिया में 1250 बेड हैं। ऐसे में इन दोनों भवन के साथ ट्रॉमा सेंटर बनने लोहिया बेड के मामले में प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान हो जाएगा, जहां

लखनऊ विकास प्राधिकरण से भूमि खरीदारी के लिए जल्द ही शासन प्रस्ताव भेजेंगे और मंजूरी मिलते ही तत्काल भूमि संस्थान के नाम परिवर्तित कराने के साथ निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें एक-दो माह का समय लगता है। निर्माण शुरू होने के बाद 24 माह के भीतर इसे पूरा करने का लक्ष्य है। हमें ट्रॉमा सेंटर के लिए यह भूमि मिली है तो इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देना चाहूंगा। प्रो. सीएम सिंह, निदेशक, लोहिया संस्थान

सड़क दुर्घटनाएं, हादसे, गोली लगना या कई अंगों की गंभीर चोट जैसे मामलों में तुरंत उपचार की जरूरत होती है। लेवल-एक ट्रॉमा सेंटर ऐसे मरीजों के लिए 247 रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी की सभी जांचों समेत उच्चस्तरीय देखभाल की सुविधा मुहैया कराता है। इसमें ट्रॉमा सर्जन, न्यूरोसर्जन, आर्थोपेडिक

सर्जन, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ और क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ हर समय उपलब्ध रहते हैं। लखनऊ प्रदेश की राजधानी होने के कारण यहां बड़ी संख्या में गंभीर मरीज रेफर किए जाते हैं। यह ट्रॉमा सेंटर पूरे क्षेत्र के लिए प्रमुख केंद्र का काम कर सकता है। गंभीर चोट के बाद शुरूआती एक घंटे (गोल्डेन आवर) में सही उपचार मिलने से मौत और स्थायी विकलांगता का जोखिम काफी कम हो जाता है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण से भूमि खरीदारी के लिए जल्द ही शासन प्रस्ताव भेजेंगे और मंजूरी मिलते ही तत्काल भूमि संस्थान के नाम परिवर्तित कराने के साथ निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें एक-दो माह का समय लगता है। निर्माण शुरू होने के बाद 24 माह के भीतर इसे पूरा करने का लक्ष्य है। हमें ट्रॉमा सेंटर के लिए यह भूमि मिली है तो इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देना चाहूंगा। प्रो. सीएम सिंह, निदेशक, लोहिया संस्थान

गोमती नगर विस्तार सेक्टर-सात में शहीद पथ किनारे लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को लेवल-एक ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए 16603.34 वर्ग मीटर जमीन आवंटित किया है। आगे की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। प्रथमेश कुमार, उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण

भर्ती परीक्षा का परिणाम आने के बाद खान सर और ज्ञान बिंदु दोनों संस्थानों के बीच छात्रों को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी। इसी वजह से तनाव की स्थिति बनी। रहमान सर ने आरोप लगाया कि जब कुछ दावों पर सवाल उठे तो गोली चलने जैसी बात सामने लाई गई।

व्या है पूरा मामला? मंगलवार को पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर बड़ी घटना से बचा जा सके। फायरिंग के दावे पर जताया संदेह रहमान सर ने घटना में गोली चलने के दावे पर भी सवाल उठाए। 5000 लड़कों का जमावड़ा लगा हुआ है। अगर वहां भगदड़ मच जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भीड़ को लेकर उठाए सवाल



रहमान सर ने खान सर को घेरा गुरु रहमान ने कहा कि यह विवाद कोई नया नहीं है बल्कि काफी समय से चला आ रहा है। उनके अनुसार अगर संबंधित लोग अपनी हरकतों में बदलाव नहीं लाएंगे तो ऐसे विवाद आगे भी सामने आते रहेंगे। उन्होंने कहा, "खान सर नौटंकी कर रहे हैं। मैं बिहार के डीजीपी और मुख्यमंत्री के साथ चर्चा से अनुरोध करता हूँ कि जिस तरह रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई है, उसी तरह खान सर की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक जगह पर 5000 लड़कों का जमावड़ा लगा हुआ है। अगर वहां भगदड़ मच जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?" भीड़ को लेकर उठाए सवाल

भर्ती परीक्षा का परिणाम आने के बाद खान सर और ज्ञान बिंदु दोनों संस्थानों के बीच छात्रों को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी। इसी वजह से तनाव की स्थिति बनी। रहमान सर ने आरोप लगाया कि जब कुछ दावों पर सवाल उठे तो गोली चलने जैसी बात सामने लाई गई।

व्या है पूरा मामला? मंगलवार को पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर बड़ी घटना से बचा जा सके। फायरिंग के दावे पर जताया संदेह रहमान सर ने घटना में गोली चलने के दावे पर भी सवाल उठाए। 5000 लड़कों का जमावड़ा लगा हुआ है। अगर वहां भगदड़ मच जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भीड़ को लेकर उठाए सवाल

गोरखपुर में सिक्सलेन और फोरलेन फ्लाईओवर का एक साथ होगा लोकार्पण, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन

गोरखपुर में ट्रांसपोर्टनगर से पैडलेगंज तक बने सिक्सलेन और देवरिया बाईपास के फोरलेन फ्लाईओवर का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ करेंगे। (जीएनएस)।

गोरखपुर। ट्रांसपोर्टनगर से पैडलेगंज की तरफ बने सिक्सलेन और देवरिया बाईपास की तरफ से बन रहे फोरलेन फ्लाईओवर का लोकार्पण एक साथ होगा। फोरलेन फ्लाईओवर का काम इसी महीने की 20 तारीख तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी इसी महीने दोनों फ्लाईओवर का लोकार्पण हो सकता है। इस बीच, सेतु निगम ने पंचमुखी हनुमान मंदिर की तरफ से देवरिया बाईपास की ओर जाने वाले साइड रोड को खोल दिया है। इससे राहगीरों को काफी राहत मिली है।

सेतु निगम ने पिछले महीने ही ट्रांसपोर्टनगर से देवरिया बाईपास के आगे पैडलेगंज की तरफ सिक्सलेन फ्लाईओवर का निर्माण पूरा करा दिया है। फ्लाईओवर पर

स्ट्रीट लाइट लगाने के साथ ही इसका परीक्षण भी करा लिया गया



है। स्वागत द्वार भी लगा दिए गए हैं। माना जा रहा था कि पहले सिक्सलेन फ्लाईओवर का लोकार्पण होगा। इसके बाद फोरलेन फ्लाईओवर का लोकार्पण किया जाएगा लेकिन अब दोनों का लोकार्पण एक साथ करने की बात कही जा रही है।

मुख्यमंत्री करेंगे लोकार्पण

पूर्वांचल के पहले सिक्सलेन

फ्लाईओवर और इससे जुड़ रहे फोरलेन फ्लाईओवर का मुख्यमंत्री



योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे। सेतु निगम ने निर्माण की गुणवत्ता के साथ ही झटका मुक्त फ्लाईओवर तैयार करने का दावा किया है। दोनों फ्लाईओवर शुरू होने के बाद देवरिया बाईपास, नहर रोड, रुस्तमपुर, मेहवा और ट्रांसपोर्टनगर में जाम की समस्या का तो समाधान होगा ही राहगीरों को कम समय में यात्रा पूरी करने का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री करेंगे लोकार्पण

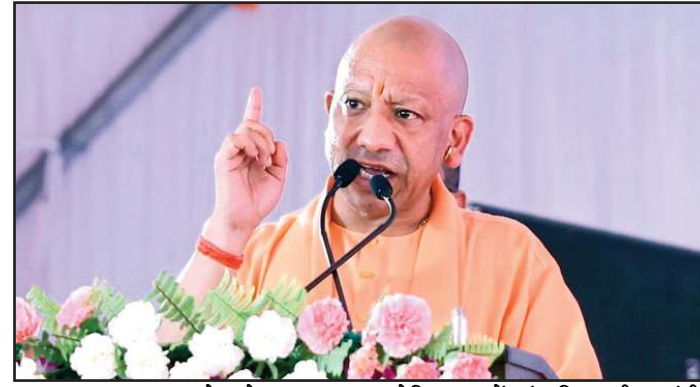
पूर्वांचल के पहले सिक्सलेन

25 प्रस्ताव पास, 17 नगर निगमों चलेंगी नई ई-बसें, जेवर एयरपोर्ट भी होगा कनेक्ट

(जीएनएस)।

लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी परिवहन को मजबूत बनाने के लिए 17 नगर निगमों और नोएडा में 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने का निर्णय लिया है। इस योजना से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं बेहतर होंगी, प्रदूषण घटेगा और जेवर एयरपोर्ट को भी परिवहन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। परियोजना पर 1852 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

यूपी में बुधवार को कैबिनेट में कुल 25 प्रस्ताव रखे गए। इसमें 24



प्रस्ताव पास हुए। प्रदेश के 17 नगर

इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी।

इन बसें का संचालन नगर क्षेत्रों के

साथ-साथ उनकी परिधि में आने वाले क्षेत्रों तक किया जाएगा, जिससे आम लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिल सकेगी।

सरकार बस डिपो और अन्य आवश्यक आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराएगी। साथ ही किराये और निविदा (बिडिंग) के बीच होने वाले अंतर की भरपाई भी सरकार करेगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से शहरी परिवहन को नई गति मिलेगी और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी।

'सीएम योगी के गांव का हूं गोली मार दूंगा', बैंक मैनेजर ने दी लोन लेने वाले कस्टमर को फोन पर धमकी

पीड़ित को मैरिज हाल बनवाने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ा भारी, तत्कालीन बैंक मैनेजर ने फोन पर पीड़ित को दिया जान से मारने की धमकी, बैंक मैनेजर ने कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गांव का रहने वाला हूं योगी जी का मेरे पर आना जाना है तुम्हारी गोली मारकर कर दूंगा हत्या। (जीएनएस)।

बाराबंकी: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां पर पीड़ित ओवरसीज बैंक के तत्कालीन मैनेजर के द्वारा पीड़ित उपभोक्ता को फोन पर धमकाने का ऑडियो सामने आया है। जिसमें तत्कालीन बैंक मैनेजर विराट कौशिक ने उसे गोली मारकर जान से मार देने की धमकी दी है। उसके साथ ही पीड़ित उपभोक्ता को धमकाया है कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गांव का रहने वाला है। शासन प्रशासन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है वह उपभोक्ता को गोली मारकर उसकी हत्या कर देगा। डरे सहमे पीड़ित ने बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर पूरे मामले पर न्याय की

इरानी के नए परमिट सिस्टम में फंसे भारत और चीन के तेल टैंकर? 300 जहाजों ने किया अफ्लाई

(जीएनएस)।

दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में शामिल होर्मुज स्ट्रेट अब एक नए विवाद के केंद्र में है। ईरान ने यहां टोल और परमिट सिस्टम लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, जिसके बाद 300 से ज्यादा जहाजों ने सुरक्षित गुजरने के लिए आवेदन किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सबसे ज्यादा आवेदन तेल टैंकरों की तरफ से आए हैं। चीन और भारत जाने वाले जहाजों की संख्या भी काफी अधिक है। इस कदम ने ग्लोबल ट्रेड, तेल सप्लाई और अमेरिका-ईरान रिश्तों को लेकर नई बहस शुरू कर दी है।

ईरान से जुड़ी नई अर्थोरिटी दृष्टिगत का दावा है कि होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने के लिए अब तक 300 से ज्यादा जहाजों ने परमिट के लिए अफ्लाई किया है। इनमें ज्यादातर ऑयल टैंकर शामिल हैं। बताया गया है कि करीब 77 फीसदी जहाज फारस की खाड़ी से निकलकर एशियाई देशों की ओर जा रहे हैं। चीन और भारत इन जहाजों के प्रमुख डेस्टिनेशन हैं। दोनों देश खाड़ी क्षेत्र से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस

गुहार लगाई है।

आपको बता दें कि पूरा मामला



जनपद बाराबंकी के देवा कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जहां पर पीड़ित सुनील कुमार पुत्र रूप नारायण निवासी ग्राम बिशुनपुर थाना देवा के द्वारा शिवा पेल्लेस एंड मैरिज लॉन बिशुनपुर में बनवाया जा रहा है। जिसके लिए पीड़ित ने देवा में स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक से 15 लाख रुपए का लोन लिया था। उस समय तत्कालीन बैंक मैनेजर विराट कौशिक के द्वारा लोन को पास किया गया था। पीड़ित द्वारा समय पर बैंक की किस्त अदा की जा रही थी। लेकिन बीते 2 जून को रात्रि करीब 9.39 मिनट पर देवा के ओवरसीज बैंक के तत्कालीन मैनेजर विराट

फोन किया गया और पैसा जमा करने की बात कही गयी। पीड़ित ने बताया कि समय पर उसकी किस्त जा रही है लेकिन बैंक मैनेजर ने कहा कि 27000 रुपए उसे तत्काल जमा करना है यदि नहीं जमा करेगा तो उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाएगी। बैंक से 15 लाख रुपए का लोन लिया था। उस समय तत्कालीन बैंक मैनेजर विराट कौशिक के द्वारा लोन को पास किया गया था। पीड़ित द्वारा समय पर बैंक की किस्त अदा की जा रही थी।

लेकिन बीते 2 जून को रात्रि करीब 9.39 मिनट पर देवा के ओवरसीज बैंक के तत्कालीन मैनेजर विराट

खरीदते हैं।

ईरान ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से कितना टोल लिया जाएगा। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स



में दावा किया गया है कि एक बड़े तेल टैंकर से करीब 20 लाख डॉलर तक टोल लिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो शिपिंग कंपनियों की लागत में भारी बढ़ोतरी होगी। इसका असर तेल की कीमतों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है। फिलहाल टोल की आधिकारिक दरों का इंतजार किया जा रहा है। दोस्त देशों को प्राथमिकता,

कौशिक जो कि लखनऊ के चिनहट ब्रांच में पोस्ट है. उनके द्वारा पीड़ित को

बैंक मैनेजर मुख्यमंत्री योगी का रौब उसे दिखाता रहा और लगातार जान से मारने की धमकी देता रहा है. दरअसल आपको बता दें कि बैंक मैनेजर विराट कौशिक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने के नियत से पीड़ित सुनील कुमार को धमकाया है. जबकि पीड़ित के द्वारा समय पर बैंक के लोन की किस्त अदा की जा रही है. पीड़ित के पास बैंक मैनेजर के द्वारा उसे धमकाने का ऑडियो भी मौजूद है, जिसको लेकर पीड़ित ने बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय से शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है.

पीड़ित ने बताया है कि जब तत्कालीन बैंक मैनेजर विराट कौशिक देवा की ब्रांच में तैनात नहीं है, तो उनके द्वारा उन्हें बिना वजह क्यों धमकाया गया है. जबकि वह समय से अपने लोन की किस्त को अदा कर रहा है. हालांकि पीड़ित के अनुसार बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने उसे आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले की जांच क्षेत्राधिकारी से कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मुख्यमंत्री योगी का उसके घर पर आना-जाना है, शासन प्रशासन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है. पीड़ित ने तत्कालीन बैंक मैनेजर से किस्त जमा करने को लेकर के बात कही, लेकिन

कि वे ईरान को किसी भी प्रकार का शुल्क न दें। अमेरिकी ट्रेजररी विभाग ने दृष्टांत पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। ट्रेजररी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ईरान वैश्विक समुद्री व्यापार से जबरन पैसा वसूलने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने साफ किया है कि अगर कोई कंपनी प्रतिबंधित संस्थाओं को भुगतान करती है तो उसे अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।

होर्मुज को लेकर बढ़ रहा अमेरिका-ईरान टकराव पिछले कुछ महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ा है। क्षेत्रीय संघर्ष और सैन्य गतिविधियों के बाद होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा बढ़ा मुद्दा बन गई।

ईरान पहले भी इस रणनीतिक समुद्री रास्ते को बंद करने की चेतावनी देता रहा है। अब टोल सिस्टम की योजना को अमेरिका चुनौती दे रहा है। दोनों देशों के बीच मध्यस्थों के जरिए बातचीत की कोशिशें हुईं, लेकिन अब तक कोई साझा समाधान नहीं निकल पाया है। इससे पूरे पश्चिम एशिया में अनिश्चितता बनी हुई है।